

जैथरा जन चौपाल वधायक ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों की लगाई क्लास

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> एटा के जैथरा में जन चौपाल का आयोजन ग्रामीणों की समस्याओं पर सीधा संवाद...
- >> धुमरी गांव में चौपाल और सीधा जनसंवाद...
- >> केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरण होने के उपलक्ष्य में धुमरी गांव में लगा दरबार...
- >> विकास यात्रा और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर चर्चा...
- >> जन चौपाल में मौजूद रहे विकासखंड और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी...
- >> प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में शिकायतों का पंजीकरण...
- >> आयुष्मान, उज्ज्वला और किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी...
- >> प्रमुख योजनाओं की रूपरेखा और प्रक्रिया...
- >> ग्रामीणों ने उठाई वधिवा पेंशन, लंबित कसितों और जमीनी विवादों की शिकायतें...
- >> जमीनी और आपसी विवादों का मुद्दा...
- >> गांव के जरूरत रास्तों और पात्रों को लाभ न मिलने का भी उठा मुद्दा...
- >> आवागमन और जलभराव की समस्याएं...
- >> वधायक सत्यपाल सहि राठौर के सख्त निर्देश शिकायतों का तत्काल संज्ञान ले अधिकार...
- >> राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई के आदेश...
- >> हर पात्र व्यक्तिगत पहुंचे लाभ समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर दिया गया जोर...
- >> आपके सवाल, हमारे जवाब...

उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत आने वाले जैथरा क्षेत्र में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। ग्रामीणों की दैनिक समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से एक विशाल जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में अलीगंज वधायक सत्यपाल सहि राठौर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए।

एटा के जैथरा में जन चौपाल का आयोजन: ग्रामीणों की समस्याओं पर

एटा जनपद के जैथरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत धुमरी में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्तिगत पहुंचाना और स्थानीय विवादों का मौके पर निपटारा करना रहा।

वधायक सत्यपाल सहि राठौर ने चौपाल की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चौपाल में ग्रामीणों ने बिना किसी संकोच के अपनी

समस्याएं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समक्ष रखीं।

धुमरी गांव में चौपाल और सीधा जनसंवाद

धुमरी गांव में आयोजित इस चौपाल में गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी बात सीधे ब्लॉक और तहसील स्तरीय अधिकारियों तक पहुंचाने का सुलभ मंच प्राप्त हुआ।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धुमरी गां

यह विशेष जन चौपाल केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सरकार द्वारा पछिले वर्षों में किए गए विकास कार्यों और जनहितकारी नीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। यदि आप सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो सरकार की 5 धांसू योजनाएं, सीधे खाते में पैसा और घर! जाने पूरी डिटेल यहां पढ़ सकते हैं।

विकास यात्रा और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर चर्चा

चौपाल में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने रेखांकित किया कि डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेंफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी पहलों ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाकर बचिवियों की भूमिका को समाप्त किया है।

जन चौपाल में मौजूद रहे विकासखंड और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख

जन चौपाल केवल राजनीतिक मंच न रहकर एक प्रभावी प्रशासनिक शक्ति साबित हुई। इसमें विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे ताकि समस्याओं का त्वरित परीक्षण किया जा सके।

- >> विकास विभाग: खंड विकास अधिकारी (BDO) शविशंकर शर्मा ने ग्राम विकास से जुड़ी शिकायतों को दर्ज किया।
- >> स्वास्थ्य विभाग: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) जैथरा के चिकित्सा अधीक्षक ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया।
- >> अन्य विभाग: कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना (CDPO) और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में शिकायतों का पंजीकरण

वभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित आवेदनों को संकलित किया और मौके पर ही संबंधित पत्रावलियों की जांच शुरू की। इससे ग्रामीणों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिली।

आयुष्मान, उज्ज्वला और किसान सम्मान नधि जैसी सरकारी योजनाओं

चौपाल के दौरान अधिकारियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) और लाभार्थी सूची (Beneficiary List 2026) देखने की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई।

अधिकारियों ने बताया कि कैसे पात्र व्यक्ति घर बैठे अपना स्टेटस (Status Check) कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता से जुड़ी जानकारी भी दी गई। ग्रामीण उद्यमी बिना गारंटी 5 करोड़ तक लोन! सरकार की नई बिजनेस योजनाएं जरूर अपने कारोबार को नया विस्तार दे सकते हैं।

प्रमुख योजनाओं की रूपरेखा और प्रक्रिया

चौपाल में निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं पर विशेष प्रकाश डाला गया:

- >> प्रधानमंत्री किसान सम्मान नधि: ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग की प्रक्रिया।
- >> आयुष्मान भारत योजना: 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनवाना।
- >> प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): पक्के मकान के लिए पात्रता व सत्यापन।
- >> जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत: हर घर नल से जल और स्वच्छता प्रबंधन।

इसी तरह की अन्य जनकल्याणकारी पहलों की समीक्षा के लिए आप MAIN NEWS HEADLINE: केसीसी, आयुष्मान कार्ड, पेंशन व आवास योजनाओं की सौभी देख सकते हैं।

ग्रामीणों ने उठाई वधिव पेंशन, लंबित कसितों और जमीनी विवादों

जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने अपनी वास्तविक परेशानियां विधायक और अधिकारियों के सामने रखीं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें सामाजिक सुरक्षा पेंशन और किसान नधि से संबंधित थीं।

कई महिलाओं ने वधिव पेंशन स्वीकृत न होने अथवा तकनीकी कारणों से मासिक कसित रुकने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं किसानों

ने पीएम किसान सम्मान निधि की पछिली कसिती खाते में न आने और बैंक खाता आधार लकि न होने की बात कही।

जमीनी और आपसी वविदों का मुद्दा

ग्रामीण क्षेत्रों में पैतृक भूमि, चकरोड पर अवैध कब्जे और आपसी सीमांकन वविदों से संबंधित मामले भी पुलिस व राजस्व विभाग के सामने प्रमुखता से उठाए गए।

गांव के जरूर रास्तों और पात्रों को लाभ न मलने का भी उठा मु

धुमरी और आसपास के ग्रामीणों ने बुनियादी ढांचे की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के प्रमुख संपर्क मार्ग और चकरोड लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही खड़जा निर्माण, नालियों की सफाई और कई जरूरतमंद परिवारों का नाम पात्रता सूची से छूटे होने की शिकायतें भी दर्ज कराई गईं। ग्रामीणों की मांग थी कि नए सरि से सर्वे कराकर छूटे हुए पात्रों को जोड़ा जाए।

आवागमन और जलभराव की समस्याएं

बारिश के दिनों में चकरोडों और गलियों में होने वाले जलभराव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ग्रामीणों ने पक्के नाले और इंटरलॉक गि सड़क निर्माण की मांग की।

वधायक सत्यपाल सहि राठौर के सख्त नरिदेश: शिकायतों का तत्का

ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अलीगंज वधायक सत्यपाल सहि राठौर ने उपस्थित अधिकारियों को कड़े लहजे में नरिदेशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन समस्याओं के नसितारण में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

वधायक ने समाज कल्याण और कृषि विभाग के अधिकारियों को नरिदेश दिया कि पेंशन और किसान सम्मान निधि की तकनीकी खामियों को कैप लगाकर तुरंत ठीक किया जाए।

राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त कार्रवाई के आदेश

जमीनी विवादों और चकरोड पर अवैध कब्जों के मामलों में विधायक ने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर मुआयना करने और नष्टिपक्ष समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

हर पात्र व्यक्तिगत पहुंचे लाभ : समस्याओं के समयबद्ध समाधान

चौपाल के समापन पर विधायक सत्यपाल सहि राठौर ने दोहराया कि सरकार का संकल्प अंतिम पंक्ति के व्यक्तिगत उत्थान है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी सूचना या प्रशासनिक देरी के अभाव में योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

यह जन चौपाल स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को पाटने में सफल रही। इस दौरान ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

आपके सवाल, हमारे जवाब

यह जन चौपाल केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी।

इस जन चौपाल की अध्यक्षता अलीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यपाल सहि राठौर ने की।

चौपाल में खंड विकास अधिकारी (BDO) शविशंकर शर्मा, सीएचसी जैथरा के चकितिसा अधीक्षक सहित कृषि, समाज कल्याण, बाल विकास परियोजना और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

ग्रामीणों ने विधवा पेंशन न मिलने, पीएम किसान सम्मान निधि की कसौटी रुकने, जर्जर चकरोडों, खंडा निर्माण और भूमि विवादों से संबंधित शिकायतें रखीं।

कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कर रुकी हुई कसौटी जल्द जारी कराई जाए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा पात्र महिलाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व बैंक विवरण के साथ आवेदन और ब्लॉक में सत्यापन कराने की जानकारी दी गई।

विधायक ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर पैमाइश करने और अवैध कब्जों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और किसान सम्मान निधि

जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई।

हां, खंड विकास अधिकारी को गांव के जरूर रास्तों, खंडा निर्माण और चकरोड मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार कर प्राथमिकता से कार्य शुरू कराने को कहा गया है।

वधायक सत्यपाल सहि राठौर ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रत्येक शिकायत का नसितारण कर आवेदक को सूचित करने का कड़ा निर्देश दिया है।